भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh

(AN ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS)

(AN INDUSTRIAL UNIT OF B.M.S.)

(RECOGNISED BY MINISTRY OF DEFENCE, GOVT. OF INDIA)

CENTRAL OFFICE : 2-A, NAVIN MARKET, KANPUR-1 • PH. & FAX : (0512) 2332222

Mob. : 09415733686, 09335621629, 09235729390 • E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

Ref: BPMS/NC JCM/ 185(8/2/L) **Dated: 19.04.2020**

श्री शिव गोपाल मिश्रा जी,
सचिव, कर्मचारी पक्ष,
संयुक्त परामर्शदात्री समिति (राष्ट्रीय)
नयी दिल्ली ।

महोदय,

सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे आल इंडिया डिफेन्स इम्प्लाइज फेडरेशन (AIDEF) के महामंत्री का दिनांक 15.04.2020 का पत्र पढ़ने को मिला जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 06 वर्षों में वर्तमान केंद्र सरकार ने कर्मचारियो की समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्य नहीं किया, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया, मंत्रिमंडल समूह (GoM) के द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा नहीं किया, दिनांक 01.01.2020 से 4% बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का निर्णय तो लिया परन्तु अभी तक भुगतान नहीं किया है, आदि। इन परिस्थितियों में आपसे आग्रह किया है कि सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाय । लगभग इसी प्रकार के एक पत्र के द्वारा उन्होने (दिनांक 18.04.2020 को) अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि सभी कर्मचारियों को संगठित होकर सरकार के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए । और इसके लिए वे अन्य संगठनों से भी सम्पर्क कर रहे हैं ।

हमारा महासंघ 'भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ' भी संयुक्त परामर्शदात्री समिति में शामिल है और कर्मचारियों के हितों के संरक्षण तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 'संवाद से संघर्ष तक' की नीति को अपनाता है, साथ ही 'उद्योग हित ' को भी ध्यान में रखता है लेकिन राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखता है । हमें तो यह स्मरण कराया जाता है कि ट्रेड यूनियन के सन्दर्भ में मालिक और मजदूर के अतिरिक्त एक तीसरा घटक है 'राष्ट्र '। सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ मजदूरों का हित भी एकात्म है। राष्ट्र खड़ा रहेगा तो मजदूर गिर नहीं सकता। राष्ट्र गिर जाएगा तो मजदूर खड़ा नहीं रह सकता। वैसे ही जब तक मजदूर खड़ा है तब तक वह राष्ट्र को गिरने नहीं देगा। मजदूर गिर जाएगा तो फिर राष्ट्र को कौन बचायेगा।

आज जब अपना राष्ट्र विश्वव्यापी 'कोरोना' महामारी से ग्रस्त है, सारे लोग एक जुट होकर इस महामारी से जीतने के लिए त्याग एवं संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे समय में हम सरकारी कर्मचारी अपनी माँगो को पूरा कराने के लिए सरकार के विरुद्ध आन्दोलन की योजना बनाये अथवा संगठित होकर सरकार का असहयोग की रूपरेखा तैयार करें- मेरी समझ से यह पाप नहीं बल्कि महापाप होगा।

contd 2

हमें तो हमेशा यह याद रखना होगा कि ट्रेड यूनियन के इतिहास में आज़ादी से पूर्व तत्कालीन शासकों से, स्वतंत्रता मिलने के बाद केन्द्र में बैठी लगभग 50 वर्षों से कांग्रेस, 20 वर्षों से भाजपा एवं अन्य राजनैतिक दलों से 'संवाद से संघर्ष तक' का क्रम जारी रहा है। ट्रेड युनियनो की प्रासंगिकता कल थी, आज है और कल भी रहेगी। इसलिए हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष या असहयोग की रणनीति को इस संक्रमण काल खंड में स्थगित रखना होगा। इस संक्रमण काल खंड में राष्ट्र अथवा सरकार के सीमित संसाधनों के उपयोग का अधिकार सर्वप्रथम शोषितों, पीड़ितों, वंचितों एवं असंगठित क्षेत्र में संलग्न लाखों-करोड़ों देशवासियो को दिये जाने की आवश्यकता है। अभी सरकारें (केंद्र/राज्य) उद्योगों को चलाने की मजबूरी के नाम पर उद्योगपतियों को खुश करने के लिए श्रम कानूनों में अनेकों छूट प्रदान कर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का उत्पीड़न कराएंगी। अत: परिस्तिथियों के सामान्य होते ही हम सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए 'संवाद से संघर्ष तक' की रणनीति अपना लेंगे, परन्तु आज नहीं। आज तो आवश्यकता है राष्ट्र हित में त्याग और समर्पण की।

वर्तमान में सम्बन्धित सरकारी विभागो/कर्मचारियों ने आवश्यकता से बढ़ कर कार्य किया है जिससे समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ा है और हमारे अस्तित्व के महत्व को बहुत गम्भीरता से समझा है। हम ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की एक भी गलती इस छवि को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है, और ये जान लीजिये कि हम सरकारी कर्मचारियों को भी भविष्य में समाज के अन्य वर्गों की सहानूभूतिपूर्वक सहयोग की परम आवश्यकता रहेगी।

देश का एक जिम्मेदार नागरिक, एक सरकारी कर्मचारी और एक संगठनकर्ता होने के नाते हमने भी सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं जैसे NPS के अधीन कर्मचारियो के लिए General Provident Fund की सुविधा, CGEGIS के अंशदान और लाभ को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर करना आदि, जिससे सरकार को दीर्घकालिक निधि और कर्मचारियो को भी लाभ मिल सके। वर्तमान समय में यह हमारे सुझाव हैं, कोई माँग नहीं है, कोई सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) नहीं है और न ही इनके स्वीकार नहीं करने पर किसी भी प्रकार के आन्दोलन या असहयोग की धमकी दी है। यह मात्र एक पारस्परिक सहयोग (responsive cooperation) है।

वर्तमान परिस्तिथियाँ हमें अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि, तथाकथित राजनैतिक सम्बद्धता अथवा पारस्परिक एवं आन्तरिक प्रतियोगिता कर सदस्यता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के विरुद्ध आन्दोलन अथवा असहयोग करने की अनुमति नहीं देती है। मेरा यह भी मानना है कि यह हम ट्रेड यूनियनो के संस्कारों की लड़ाई लड़ने का भी अवसर नहीं है ।सरकार से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वह एक आदर्श नियोक्ता (Model Employer) बने लेकिन आज सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे भी आदर्श कर्मचारी के रुप में अपने आपको प्रस्तुत करें ।

अत: मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वैश्वीक संकट की घड़ी में यदि किन्ही कारणों से आप सरकार का सहयोग नहीं कर सकें तो किसी के उकसावे के प्रभाव में न आकर, सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आन्दोलन अथवा असहयोग का वातावरण बनाने वाले लोगों/संगठनो का नेतृत्व नहीं करने की कृपा करेंगे ।

सादर,

आपका सहयोगाकांक्षि

M.K Singh

(मुकेश सिंह)

महामंत्री